राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

# हलधर किसान

डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24

Email id: haldharkisankgn@gmail.com

RNI NO. MPHIN/2022/85285

वर्ष 04 अंक 01 | मार्च 2025 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

## गेहूं, धान और मोटे अनाज जैसी रबी फसलों के लिए खरीद लक्ष्य तय, 3.1 करोड़ टन गेहूं खरीदी करेगी सरकार

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्लीः सरकार ने अप्रैल से शुरू होने वाले 2025.26 रबी विपणन सत्र के लिए 3.1 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया। कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2024.25 (जुलाई.जून) में 11. 5 करोड़ टन रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है, इसके बावजूद खरीद लक्ष्य कम है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के खाद्य सचिवों के साथ हुई बैठक में गेहूं, धान और मोटे अनाज जैसी रबी फसलों के लिए खरीद लक्ष्य तय किया गया। विचार.विमर्श के बाद, आगामी 2025.26 विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 3.1 करोड़ टन, चावल 70 लाख टन और मोटे अनाज 16 लाख टन निर्धारित किया गया। राज्यों से आगामी विपणन सत्र में गेहूं और चावल की खरीद को अधिकतम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा गया। राज्यों से फसलों के विविधीकरण और आहार चलन में पोषण बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए मोटे अनाज की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा गया। अप्रैल से शुरू होने वाले 2025.26 रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी हों, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां गेहूं की खरीद करती हैं। सत्र 2024.25 में सरकारी गेहूं खरीद तीन से 3.2 करोड़ टन के लक्ष्य के मुकाबले 2.66 करोड़ टन तक पहुंच गई। हालांकि यह 2023.24 में खरीदे गए 2.62 करोड़ टन से अधिक है, लेकिन यह उस वर्ष के 3.41 करोड़ टन लक्ष्य से कम है। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जन पोषण केन्द्रों से संबंधित कई अन्य पहलों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों, एफसीआई, भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

## आटा मिलों ने की गेहूं बोर्ड के गठन की मांग

देश में आटा मिलों की शीर्ष संस्था रोलर्स फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफइंडिया ने सरकार से गेहूं आधारित कारोबार के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के अलावा नीति मार्गदर्शन और बाजार विस्तार के अवसर प्रदान करने के लिए एक गेहूं बोर्ड स्थापित करने की मांग की।

आरएफएमएफआई के अध्यक्ष नवनीत चितलांगिया ने यहां आटा मिल कारोबार पर दो दिन के सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुये कहा हमारा उद्योग एक आर्थिक क्षेत्र से कहीं अधिक है, यह खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है, रोजगार में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक आवश्यक शक्ति है।

उन्होंने कहा कि इस उद्योग की क्षमता को उजागर करने और बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित गेहूं नीति होनी चाहिए।

इस अवसर पर लोकसभा सांसद एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के संस्थापक महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने आरएफएमएफओआई को इस मुद्दे पर समुचित सहयोग का भरोसा देते हुए गेहूं उपभोग के बारे में संगठन से गेहूं बोर्ड के प्रस्ताव का विस्तृत खाका तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव उचित और अच्छा रहा तो वह 18 महीने के अंदर गेहूँ बोर्ड बनवाने में पूरी मदद करेंगे। दो दिन के इस कार्यक्रम का पहला दिन था। इस सम्मेलन में देश.विदेश से आटा मिल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि और नीति नियामक आमंत्रित किये गये हैं। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और आधुनिक बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें अनाज भंडारण की नयी तकनीक जैसे विषय भी शामिल है।

## टैरिफ वार: अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर पर चीन ने लगाया 15 प्रतिशत तक का शुल्क

**हलधर किसान. नई दिल्ली।** अमेरिका के शुरु किए गए टेरिफ बढ़ोत्तरी फार्मूले पर चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 15 प्रतिशत का शुल्क लगाने का आदेश जारी कर जवाब दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। भारत के लिए यह चुनौती और अवसर दोनों ला सकती है, खासकर आईटी और फार्मा कंपनियां।

चीन ने कई अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15 फीसदी अतिरिक्त टैरिफलगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ10 मार्च से लागू हो जाएगा। चीनी वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की है। ये टैरिफ चिकन, गेहूं, मक्का और कपास सहित प्रमुख अमेरिकी निर्यातों पर लागू होंगे। इस फैसले से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहा ट्रेड वॉर और बढ़ जाएगा। चीन का यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी उत्पादों के आयात पर ड्यूटी को बढ़ाकर 20 फीसदी करने के आदेश के बाद आया है। चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका में उगाए गए चिकन, गेहूं, मक्का और कपास के आयात पर 15 फीसदी अतिरिक्त टैरिफलगेगा। ज्वार, सोयाबीन, सूअर का मांस, बीफ, समुद्री भोजन, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ10 फीसदी बढ़ाया जाएगा।

**बढ़ रहा ट्रेड वॉर**

अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयात पर व्यापक शुल्क लागू कर दिये हैं। इन नए शुल्कों से अमेरिकी टैरिफऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, इससे बिजनेसेज और विदेशी सरकारों में खलबली मची हुई है। कनाडा और मेक्सिको से सभी आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लग गया है। जबकि चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ देश की समस्याओं को ठीक कर सकता है।

व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निष्पक्ष, मुक्त, पारस्परिक व्यापार के लिए एक योजना की घोषणा की है। अमेरिका अब दूसरे देश की ओर से बहुत ज्यादा कीमत वसूले जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी हमारे व्यापारिक साझेदार अपने बाजारों को अमेरिकी निर्यात के लिए बंद रखते हैं।

**कनाडा ने भी अमेरिका पर लगाया जवाबी टैरिफ**

कनाडा ने कहा कि वह अमेरिका से 125 अरब कनाडाई डॉलर के अतिरिक्त आयात पर जवाबी टैरिफलगाएगा। इसकी शुरुआत 30 अरब कनाडाई डॉलर के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ से हो गई है। कनाडा के इस एक्शन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने कहा है कि अगर डोनाल्ट ट्रंप कनाडाई वस्तुओं पर अपने प्रस्तावित टैरिफके साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा टैरिफभी लागू रहेगा। ट्रुडो ने आगे कहा हमारे टैरिफतब तक लागू रहेंगे, जब तक कि अमेरिकी ट्रेड एक्शन वापस नहीं ले लिया जाता और यदि अमेरिकी टैरिफ समाप्त नहीं होते हैं, तो हम कई नॉन.टैरिफउपायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रांतों और क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं।

## अमेरिकी टैरिफ से भारत पर क्या होगा असर?

भारत से अमेरिका को कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है साल 2023.24 में भारत का कृषि निर्यात 48.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में चावल, चीनी, मसाले, कपास वगैरह शामिल हैं। हालांकि, अब जल्द ही अमेरिका भारतीय उत्पादों पर भी टैरिफबढ़ा सकता है। इस बीच, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि यहां वह अमेरिकी अफ़सरों से मुलाकात करके टैरिफका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच, व्यापारिक समझौतों पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, फ़िलहाल दोनों देश इस बिंदु पर काम कर रहे हैं कि कैसे अमेरिकी टैरिफके प्रभाव को भारत पर कम किया जा सके। इस बारे में भारत अमेरिकी मांगों पर भी विचार कर रहा है। इनमें अमेरिका ने भारत से कुछ उत्पादों पर टैरिफकम करने की मांग की है। इसके अलावा अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत में बाजार तैयार करना भी शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादातर घरेलू बाजार पर निर्भर हैं। ये अमेरिका के ऊंचे टैरिफके असर से कुछ हद तक बच सकते हैं। भारतए उसके बाद दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, ऐसे देश हैं जिन पर अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे सकता है। अगर अमेरिका भारत से आम आयात करता है और उस पर 5 प्रतिशत टैरिफलगाता है, जबकि भारत अमेरिका से सेब आयात करता है और उस पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। इस अंतर के चलते अमेरिका भारत पर जवाबी टैरिफलगा सकता है। यह एक साधारण उदाहरण है। असल स्थिति और भी जटिल हो सकती है।

टैरिफ लगाने के फायदे क्या हैं? टैरिफसे सरकार को राजस्व मिलता है। दूसरा देशी कंपनियां, विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की कंपनियां मोबाइल फोन बनाती हैं। यह कंपनी अपने फोन अमेरिका बेचने पहुंचाती है। जबकि अमेरिका में भी बहुत सारी कंपनियां फोन बनाती हैं। अगर चीनी कंपनी वहां अपने सस्ते और आकर्षक फोन बेचना शुरू कर दे तो अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। इसके साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा।

ऐसे में रेवेन्यू हासिल करने और घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए सरकार टैरिफ लगाएगी। टैरिफ लगाने से चीनी फोन महंगे हो जाएंगे और फोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां उनका मुकाबला कर पाएंगीं। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफलगाने वाले देशों में भारत शामिल भारत सबसे ज्यादा टैरिफलगाने वाले देशों में शामिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1990.91 तक औसत टैरिफ125 प्रतिशत तक था। उदारीकरण के बाद यह कम होता चला गया। 2024 में भारत का एवरेज टैरिफरेट 11.66 प्रतिशत था।

ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफरेट में बदलाव किया। द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टैरिफके 150 प्रतिशत, 125 प्रतिशत और 100 प्रतिशत वाली दरों को समाप्त कर दिया है। अब भारत में सबसे ज्यादा टैरिफरेट 70 प्रतिशत है। भारत में लग्जरी कार पर 125 प्रतिशत टैरिफथा, अब यह 70 प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसे में साल 2025 में भारत का एवरेज टैरिफरेट घटकर 10.65 प्रतिशत हो चुका है।

आमतौर पर सभी देश टैरिफलगाते हैं। किसी देश में इसका रेट कम और किसी में ज्यादा हो सकता है। हालांकि, बाकी देशों से तुलना की जाए तो भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है।

# जीनोम एडिटिंग के जरिए सब्जियों की नई वैरायटी तैयार, आईआईएचआर के वैज्ञानिक प्रदर्शनी में करेंगे प्रयोग का प्रदर्शन

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

**भोपाल।यदि सबकुछ ठीक रहा तो, जल्द ही बाजार में टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता, अनार जैसी सब्जियां और फल देखकर लोग अपने आप आकर्षित होकर इनकी खिंचे चले जाएंगे।ये सब्जियां एकदम चमचमाते नजर आएगी, लेकिन यह पारंपरिक नही, बल्कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर) बेंगलुरु द्वारा विकसित फल और सब्जी होंगे जो एक नई किस्म है जो कि विटामिन डी से भरपूर है और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक नेशनल प्रोग्राम के तहत हो रहे प्रोजेक्ट में 16 किस्मों की सब्जियां, फलों और मसालों पर काम कर रहा है, जबकि आईआईएचआर इन सब्जियों के जीन अनुक्रमों की एडिटिंग पर काम कर रहा है।**

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक जीनोम एडिटिंग की मदद से सब्जियों और फलों की नई वैरायटी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए संस्थान में 30 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्र की स्थापना की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता और अनार के जीन अनुक्रम को संपादित करने का काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील किस्में विकसित की जा सकें।

निदेशक तुसार कांति बेहरा ने बताया हमें दो साल में नई किस्में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था और काम जोरों पर चल रहा है। वैज्ञानिक पोषक तत्वों से भरपूर नई किस्मों को विकसित करने पर काम कर रहे हैं।

यह सक्रमण का चरण है, जहां हम उच्च उत्पादन वाली किस्मों से पोषक तत्वों से समृद्ध किस्मों की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो जैविक और अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी हों और आर्थिक रूप से भी मूल्यवान हों। इस प्रयोग के तहत, हम कुछ पारंपरिक और कम ज्ञात फसलों को पोषक तत्वों से समृद्ध बना रहे हैं और इन्हें जलवायु परिवर्तन और रोगों के प्रति अधिक सहनशील बना रहे हैं।

इन किस्मों को चुनने के कारण के बारे में बेहरा ने स्पष्ट किया, हमने उन फल और सब्जियों को चुना है, जिनकी जीन संरचनाएं पहले से अच्छी तरह से पहचानी और अनुक्रमित की गई हैं।

इस प्रयोग में गरीब आदमी का सेब, टमाटर भी विटामिन डी से समृद्ध किया जाएगा, जबकि पपीता, मिर्च, अंगूर और अनार जैसी अन्य किस्में जीनोमिक संपादन के माध्यम से वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी बनाई जाएंगी।

## क्या कर रहे वैज्ञानिक?

आईआईएचआर के वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि जीनोम संपादित फसलें पूरी तरह से जीएम (जैविक रूप से परिवर्तित) फसलों से अलग हैं, जिनका भारत में विरोध किया गया है। उन्होंने कहा, जीएम फसलों में पौधे में बाहरी डीएनए डाला जाता है, जबकि जीनोम संपादन में केवल पौधे के मौजूदा जीन को संशोधित किया जाता है या तो इसे इसके अपने जीन से उत्परिवर्तित करके या विशेष रंगद्रव्य वृद्धि के द्वारा इसे अधिक पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है। इस बदलाव को पहले फूलगोभी में देखा जा चुका है, जिसमें सफेद रंग के बजाय बैंगनी और पीले रंग के फूल हो गए हैं। यह रंगद्रव्य की वृद्धि के कारण है, जो एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिनों से भरपूर है। इसी तरह, सुनहरे पीले रंग का टमाटर विटामिन डी के समृद्ध होने का प्रतीक है।

**नई किस्मों को भी लॉन्च किया जाएगा**

27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक अपने हेयरगढ़त्ता परिसर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित करेगा, जिसमें विभिन्न किस्मों के फलों, सब्जियों और बागवानी प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए बागवानी. पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका थीम पर आधारित इस मेले में देशभर से एक लाख दर्शकों के आने की संभावना है। नई किस्मों के तरबूज, एवोकाडो, लौकी और मिर्च के अलावा, विटामिन डी से समृद्ध मशरूम और ड्रैगन फ्रूट के पाउडर फ्लेवर भी लॉन्च करेगा। 200 से अधिक स्टॉल्स में आईआईएचआर और निजी कंपनियां बागवानी क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और विकास को प्रदर्शित करेंगी।

# बौराए आमः भुनगा व मिज कीट से बचाए, नहीं तो होगी क्षति

**हलधर किसान डेस्क.**

इन दिनों आम के पेड़ों पर बौर लगने लगे है जो फलों के राजा आम की आवक का संदेश दे रहे है। इसी समय भुनगा कीट पत्तियों व छोटे फलों को रस चूस कर क्षति पहुंचाते हैं, इनसे प्रभावित होकर छोटे फल गिर जाते हैं। यह कीट मधु की तरह का पदार्थ विसर्जित करते हैं, जिससे पत्तियों पर काले रंग की फफुंद जम जाती है। फलस्वरुप पत्तियों द्वारा हो रही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार से आम के बौर में लगने वाला मिज किट मंजरियों एवं तुरंत बने फलो तथा बाद में मुलायम कोपलों में अंडे देती हैं। जिसकी सूंडी अंदर ही अंदर खाकर क्षति पहुंचाती हैं। प्रभावित भाग काला पड़ कर सूख जाता है। यह जानकारी जिला उद्यान अधिकारी ने दी। वैज्ञानिकों ने यह सलाह भी दिया है कि बौर जब पूर्ण रूप से खिले हों तो उस अवस्था में कम से कम रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। जिससे पर.परागण क्रिया प्रभावित न हो सके। वर्तमान समय में आम के पेड़ों पर बौर लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में आम के बौर में खर्रा व भुनगा कीट का प्रकोप तेजी से फैलेगा। इससे आम के बौर को खतरा बढ़ जाएगा। समय रहते अगर बागवानों ने सावधानी नहीं बरती तो बौर तो झड़ेंगे ही साथ ही साथ प्रभावित फलों का भी नुकसान होगा। आम के बौर में टिकोरे ही नहीं लगेंगे। ऐसे में समय से छिड़काव व सुरक्षा ही आम के बौर के बचाव का बेहतर साधन है। जनवरी का पहला पखवारा बीत चुका है। कभी मौसम गर्म तो कभी सर्द हो रहा है। ऐसे में आम के बौर के प्रभावित होने की संभावना है। बौर में खर्रा रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

### ऐसे करें नियंत्रण

भुनगा एवं मिज कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली लीटर प्रति लीटर पानी या क्लोरपाइरीफास 2.0 मिली प्रति लीटर पानी अथवा डायमेथोएट 2.0 मिली प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

### खैरा रोग का प्रकोप

खैरा रोग के प्रकोप से ग्रसित फल एवं डंठलों पर सफेद चूर्ण के समान फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। प्रभावित भाग पीले पड़ जाते हैं। साथ ही मंजरियां सूखने लगती हैं।

### ऐसे करें बचाव

रोग से बचाव को ट्राइडोमार्क 1.0 मिली प्रति लीटर या डायनोकेप 1.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से भुनगा कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जा रहे घोल के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बागों में जब बौर पूर्ण रूप से खिला हो तो उस अवस्था में कम से कम रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। ताकि परागण की क्रिया प्रभावित न होने पाए।

## भारत को हरित क्रांति के उत्पादन.केंद्रित दृष्टिकोण से कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र.केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता

रत को हरित क्रांति के उत्पादन.केंद्रित दृष्टिकोण से कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र.केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

भा आजादी से कुछ दशक पहले कृषि की विकास दर कम थी। स्वतंत्रता के समय पश्चिम में मुख्य खाद्य उत्पादक क्षेत्र (विभाजन के कारण) खो गए थे और खाद्य सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता बन गई थी। 1940 के दशक की शुरुआत में बंगाल में अकाल पड़ा था। इसके कारण भारत ने खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ उत्पादन.केंद्रित दृष्टिकोण शुरू किया।

बड़े बांधों का निर्माण किया गया। कृषि की जाने वाली क्षेत्र 118 मिलियन एकड़ (1950 में) से बढ़कर 1970 में 140 मिलियन एकड़ हो गया और यह तब से स्थिर है। 1950 और 1960 के बीच भारत के खाद्य उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में बाद की घटनाओं ( लगातार दो युद्ध और एक के बाद एक सूखे) ने हरित क्रांति को जन्म दिया, जिसने खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। इसने गहन कृषि की शुरुआत की, जहां भूमि की प्रति इकाई उपज बढ़ाने के लिए अधिक निवेश (पानी, कीटनाशक, उच्च उपज वाले बीज) का उपयोग किया गया। जाहिर तौर पर यह एक दशक के भीतर सफल हो गयाए क्योंकि भारत ने (1970 के दशक तक) भोजन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी और खाद्य आयात बंद कर दिया गया था। हालांकि इससे देश में पोषण संबंधी सुरक्षा नहीं मिली क्योंकि व्यापक स्तर पर आज भी कुपोषण व्याप्त है।

उत्पादन.केंद्रित कृषि ने एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है जो मिट्टी, भूजल और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करता है। मृदा क्षरण और मृदा स्वास्थ्य में कमी एक समस्या बन गई है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने भी मिट्टी के क्षरण में योगदान दिया है। अब हमें एक पारिस्थितिकी तंत्र केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। उत्पादन.केंद्रित दृष्टिकोण में पारिस्थितिकी तंत्र की समझ का अभाव है। पारिस्थितिक तंत्र.केंद्रित दृष्टिकोण में उत्पादन प्रणाली को एक पारिस्थितिकी तंत्र के सबसेट के रूप में देखा जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र से संसाधन प्राप्त करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोग करता है और इसमें अपशिष्ट भी डालता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं होती हैं और उत्पादन. केंद्रित दृष्टिकोण इसे स्वीकार नहीं करता है।

एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता लगभग आधी सदी से है, लेकिन अब इस संकट की मान्यता अधिक है क्योंकि हितधारक कृषि.पारिस्थितिकी के बारे में बात करने लगे हैं।

भारत में कई राज्यों ने इससे संबंधित पहल किए हैं, जिन्होंने

**संपादकीय**

कृषि.पारिस्थितिकी पर विचार करने और विकल्प खोजने का प्रयास किया। हालांकि संस्थागत रूप से कृषि में लगने वाले संसाधन, बाजारों और अन्य अंतर्संबंधों तक पहुंच के संदर्भ में भारत का अधिकांश बुनियादी ढांचा हरित क्रांति प्रतिमान को आगे बढ़ाने और औद्योगिक कृषि का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। क्या एक बेहतर, टिकाऊ रूप के पक्ष में उत्पादन.केंद्रित दृष्टिकोण को त्यागना संभव है।

यह बदलाव धीमा रहेगा। हरित क्रांति अपनी शर्तों पर सफल रही क्योंकि इसने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात को कम करने के अपने उद्देश्यों को पूरा किया। इसकी सफलता के कारण यह संस्थागत रूप से जड़ जमा चुका है और इसे तोड़ना कठिन है। जैविक या प्राकृतिक खेती, चावल गहनता प्रणाली (एसआरआई), संरक्षण कृषि या गैर.कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) सहित पिछले तीन दशकों में सभी स्थायी कृषि पहलों को केवल सीमित नीतिगत समर्थन प्राप्त हुआ है। उनका विस्तार नहीं किया गया है। उनका कवरेज सकल फसली क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

एनपीएम कृषि के लिए कम लागत वाला विकल्प है। किसान और सरकार एनपीएम के लागत पहलू और स्थानीय रूप से उपलब्ध इनपुट पर इसकी निर्भरता को समझते हैं। लेकिन कृषि गतिशील है और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कम लागत होने के साथ.साथ एनपीएम श्रम प्रधान भी है। श्रम की कमी का सामना कर रही एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एनपीएम विधियों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं।

हमें इन सबकों से सीख लेकर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जहां पर्यावरण संकट सबसे गंभीर है। इसका अर्थ है फसल विविधीकरण, मिट्टी में निवेश, अनुसंधान और स्थानीय रूप से उपयुक्त बीज और सबसे महत्वपूर्ण, कृषि विस्तार प्रणाली जिसके द्वारा किसानों को योजनाओं, सेवाओं, संसाधन आदि के बारे में तकनीकी सलाह प्रदान की जाती है। यह भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति की प्रगति का श्रेय काफी हद तक ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विस्तार प्रणाली को दिया जा सकता है। यह अब लगभग निष्क्रिय हो गया है। हमें इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है।

# गज पर सवार होकर आएंगी मां दूर्गा, 30 मार्च से शुरु होंगे चैत्र नवरात्र

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

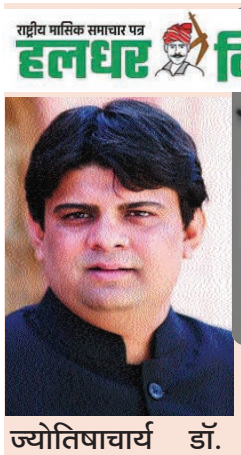

**ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी)**

अजमेर। माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र 3 मार्च से शुरु होने जा रहा है। नवरात्र के दौरान भक्तजन नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर धर्म और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। देवी पुराण के अनुसार इस दौरान मां दुर्गा धरती पर वास करती हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शामं 4 बजकर 27 मिनट पर शुरु हो रही है। वहीं, तिथि का समापन 3 मार्च को दोपहर 12 बजकर 49 मिनट होगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्र 3 मार्च से शुरु होंगे और अगले महीने यानी 7 अप्रैल को पर्व का समापन होगा। इस दिन प्रतिपदा तिथि 3 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 13 मिनट से लेकर 1 बजकर 22 मिनट तक है। इस दौरान कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा.अर्चना करें। चैत्र नवरात्र घटस्थापना तिथि पर वार्थ सिद्धि योग और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का भी संयोग है। इन योग में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होगा।

मां दुर्गा का आगमन शशि सूर्य गजरुढा शनिभौमै तुरंगमे। गुरौशुक्रेच दोलायां बुधे नौकाप्रकीर्तिता।।गजेश जलदा देवी क्षत्रभंग तुरंगमे। नौकायां कार्यसिद्धिस्यात् दोलायों मरणध्रुवम।। यह श्लोक देवीपुराण में निहित है। रविवार के दिन जगत की देवी मां दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। गज पर सवार होकर मां दुर्गा के आगमन को शुभ माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता मिलती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं।

### चैत्र नवरात्रि 2025 की तिथि

इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। वहीं 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के साथ हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होगा और गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा।

इस बार नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों रविवार को हो रहा है, जिससे मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और इसी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी पर माता का आगमन बेहद शुभ माना जाता है, जो अच्छे वर्षा चक्र, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। मान्यता है कि देवी की सवारी से आने वाले समय की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, जिसमें प्रकृति, कृषि और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होते हैं।

**कलश स्थापना मुहूर्त**

प्रतिपदा तिथि प्रारंभः 29 मार्च 2025 शाम 4.27 बजे प्रतिपदा तिथि समाप्तः 30 मार्च दोपहर 12. 49 बजे होगा।

कलश स्थापना का शुभ मुहूर्तः सुबह 6. 13 बजे से 10. 22 बजे तक

अभिजीत मुहूर्तः दोपहर 12. 01 बजे से 12. 50 बजे तक

कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है।

### वर्ग पहेली-8

**बाएं से दाएं**

1. हमेशा (3)
3. लोकोक्ति (4)
6. केवल फल खाना (4)
8. सभ्यता का आरंभिक काल (4)
9. औषध (3)
11. धान के रंग का (2)
13. मान जाना, निरुत्तकर होना (5)
16. निमौरी नामक फल का वृक्ष (2)
17. स्वजन्मा, स्वयं पैदा होने वाला (3)
19. प्रतिभाशाली, प्रारब्ध (4)
20. भ्रमित करना (4)
23. बलवा करने वाला (4)
24. अस्थि पंजर (3)

**ऊपर से नीचे**

2. दिनचर्या की सूची, डायरी (4)
3. हुनर (2)
4. आश्चर्य और दुख सूचक शब्द (2)
5. वर देने वाला (3)
6. फल देने वाला, लाभकारी (5)
7. खंदक (2)
8. सहारा, टेका (3)
10. जल (2)
12. मूर्च्छित होना, मूर्छा आना (5)
14. कटि (3)
15. संध्या, सांझ (2)
16. आकाश में तारों के मध्य सफेद मार्ग (4)
17. सुर (2)
18. हल्की गरम राख (3)
21. दाना, सूजी (2)
22. माता, मां (2)

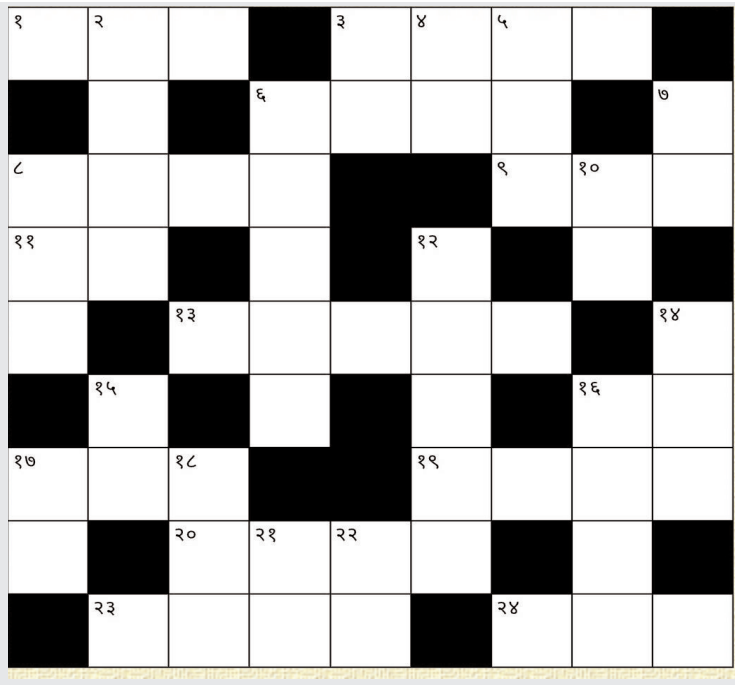

**वर्ग पहेली 7 का सही उत्तर**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ दे | २ व | र | | ३ जा | ४ न | ५ का | र | |
| | सी | | ६ क | ल | क | ल | | ७ को |
| ८ ज | य | का | र | | | ९ का | १० लि | ख |
| ११ न | त | | म | | १२ श | | पि | |
| क | | १३ अ | ज | वा | य | न | | १४ क |
| | १५ त | | ला | | न | | १६ म | हा |
| १७ सु | ले | १८ ख | | | १९ क | म | लि | नी |
| रा | | २० स | २१ भा | २२ क | क्ष | | न | |
| | २३ पा | रा | व | त | | २४ श | ता | यु |

द गैडवाल

# उत्तराखंड में अन्य राज्य के लोग नही खरीद सकेंगे कृषि भूमि, 11 जिलों में धामी सरकार ने लागू किए नए भू.कानून

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

**देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में देश के अन्य राज्यों के लोगों के लिए भूमि खरीदना अब आसान नही होगा। सरकार के संशोधित भू-कानून के चलते अब कड़े नियम लागू किए गए है। विधानसभा में धामी सरकार का संशोधित भू.कानून ध्वनिमत से पारित हो गया है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सरकार ने सदन के पटल पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950(अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 21) यथा उत्तराखंड राज्य में प्रवृत्तद्ध में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया।**

**विधेयक में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए राज्य के बाहर से व्यक्ति के भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है। इन जिलों में उद्योग एव अन्य उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली भूमि का निर्धारित से अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।**

देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए धामी सरकार ने उत्तराखंड में नया भू.कानून सदन से पास कर दिया है। सख्त भू कानून लागू होने के बाद अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लग जाएगी और राज्य के मूल स्वरूप भी सुरक्षित रहेंगे। भू.कानून नगर निगमए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्र की सीमा में आने वाले और समय.समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होगा। कोई व्यक्ति, समिति या निगमित निकाय उत्तराखंड राज्य के केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में ही कृषि या अध्ययन एक परियोजनाओं के लिए, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद भूमि ले सकेगा।

इस भूमि का उपयोग केवल कृषि या उद्यानिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। यदि व्यक्ति या समिति द्वारा शपथ पत्र में उल्लेख किए गए भूमि उपयोग में किसी भी तरह का परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे में यह भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। भू.कानून संशोधन के बारे में सीएम धामी ने बताया कि जन भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड के संसाधनों को भू.माफिया से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।

## निवेशकों का भी रखा गया ध्यान

उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही मैदानी इलाके भी हैं और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग.अलग हैं। वहींए प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भू.सुधार की नींव रखी है। इसमें अभी आगे और भी काम किया जाएगा। इस कानून से लागू होने के बाद भू.माफियाओं को

पहचानने में मदद मिलेगी।

## 2022 में समिति का गठन किया गया था

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने के प्रयोजन से उनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को देखते हुए कानून में बदलाव किया जा रहा है। धामी सरकार जनता की मांग के अनुसार सशक्त भू.कानून के लिए 3 साल से काम कर रही थी। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था।

## भूमि खरीद से पहले सत्यापन के निर्देश दिए गए थे

इस समिति ने 5 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने इस रिपोर्ट में सशक्त भू.कानून को लेकर 23 सिफारिश की थी। सरकार ने समिति की रिपोर्ट और संस्कृतियों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय प्रवर समिति का गठन किया था। इससे पहले कृषि और उद्यानिकी के लिए भूमि खरीद की अनुमति देने से पहले खरीदार और विक्रेता का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए थे।

## सिर्फएक बार खरीद सकेंगे जमीन

इस कानून के लागू होने के बाद कुछ खास बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के अनुसार हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में राज्य के बाहरी व्यक्ति कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर बाहरी राज्यों के व्यक्ति जीवन में एक बार आवासीय प्रयोजन के लिए ढाई सौ वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकेगा। इसके लिए उन्हें अब अनिवार्य शपथ पत्र देना होगा। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीद के नियम यथावत रहेंगे।

**शासन स्तर से लेनी पड़ेगी अनुमति**

हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कृषि और उद्यानिकी की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शासन से ही अनुमति लेना आवश्यक होगा। भू.कानून में 11 जनपदों में 12.5 एकड़ भूमि की सीलिंग खत्म कर दी गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी 12.5 एकड़ जमीन खरीदने से पहले इसके प्रयोजन के लिए संबंधित विभाग को आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करना होगा। तब शासन स्तर से अनुमति मिल सकेगी।

हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आसमान छू सकते हैं दाम

खरीदी गई भूमि का निर्धारण निर्धारित से अन्य उपयोग नहीं करने के संबंध में खरीदार को रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा। पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद की भी निगरानी की जाएगी। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। वहीं, अब यह भी माना जा रहा है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जमीन खरीदने की छूट होने के चलते इन दोनों जिलों में जमीनों के दाम आसमान छू सकते हैं।

## भू.कानून उल्लंघन के 599 मामले सामने आए

प्रदेश में पिछले दिनों भू कानून उल्लंघन के 599 मामले सामने आए, जिनमें से 572 मामलों में कोर्ट में वाद चल रहे हैं, जबकि अन्य निस्तारित हो चुके हैं। इस अभियान के दौरान 9.47 एकड़ भूमि सरकार में निहित हुई है।

2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने बढ़ाई थी छूट

पिछले 23 सालों में उत्तराखंड के भू.कानून में कई बाद बदलाव किए गए। वर्ष 2002 में नारायण दत्त तिवारी सरकार ने भू.कानून बनाया था और फिर 2004 में इसमें सख्त संशोधन किए गए। भू.कानून में सबसे ज्यादा छूट वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने बढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर भी उत्तराखंड में यूपी का कानून चल रहा था। जिसके तहत राज्य में जमीन खरीदने को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी।

जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भू.कानून लागू किया जा रहा है। जनभावनाएं जिस तरह के सख्त भू.कानून के पक्ष में थींए उसी अनुरूप इसमें प्रावधान किए गए हैं। इस ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड के संसाधनोंए सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो पायेगी।

## क्यों उठ रही भू कानून की मांग?

दरअसल उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है, लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं। इसके बाद लगातार भू कानून की मांग उठ रही थी।

संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा एक्स पर भू-कानून को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा राज्य संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार। प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और

### नए भू कानून में क्या है खास?

.त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त किए गए

. हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड नहीं खरीद पाएंगे

.पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती होगी

. जमीनों की खरीदारी के लिए अब जिलाधिकारी नहीं दे पाएंगे अनुमति

. प्रदेश में जमीन खरीद के लिए बनेगा पोर्टल

. पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच जमीन खरीद का भी जवाब होगा

. जमीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा

. सभी डीएम को नियमित रूप से राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट देनी होगी

.नगर निकाय सीमा के अंतर्गत जमीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत ही प्रयोग कर पाएंगे

. जमीन का इस्तेमाल अगर नियमों से हटकर किया गया तो इसे सरकार में निहित किया जाएगा



उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू.कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

## एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान/ इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म किसान प्लस टीवी पर कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित हो रहा है।

अगर आप भी कृषि पत्रकारिता में रूचि रखते है तो हमारे न्यूज चैनल सहित अखबार से जुड़ने के लिए हमारे वाट्सअप नंबर(88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

# दुबई के बाजार में भारतीय मसालों की महक 129 देशों के बीच खाद्य उद्योग को मिला बढ़ावा

**दुबई:** विश्व की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनियों में से एक, गल्फूड 2025 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शानदार तरीके से आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 129 देशों के 5,500 से अधिक प्रदर्शक भाग लिया, इस वैश्विक खाद्य व्यापार में भारत के खाद्य पदार्थों के प्रदर्शन को भी खासी सराहना मिली।

इस प्रदर्शनी में भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिसमें 370 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें 122 कंपनियां छह प्रमुख उद्योग संघों के तहत जबकि 248 स्वतंत्र प्रदर्शक शामिल रही। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन एपीडा, एमएपीडा, भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद एफआईइओ और आई ओपीईपीसी हैं।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। श्री पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है, निवेश को आकर्षित कर रहा है और भविष्य के लिए तैयार खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपना रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत की भागीदारी नए बाजारों के विस्तार और वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस दौरान महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन ने भी भारत की वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया।

## भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने की पहल

इस वर्ष गल्फूड 2025 में भारत की भागीदारी स्थिरता, प्रौद्योगिकी.संचालित आपूर्ति श्रृंखलाओं और उत्पाद विविधीकरण पर केंद्रित है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भारतीय कंपनियों के लिए बी2बी बैठकों, नेटवर्किंग कार्यक्रमों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन किया है। भारतीय प्रदर्शकों को ब्रांडिंग सहायता, बाजार अंतर्दृष्टि और खरीदारों से जुड़ने के अवसर दिए जा रहे हैं।

## भारत.यूएई व्यापार संबंधों को नया आयाम

भारत.यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत अमेज़न यूएई और नून जैसे ई.कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। वर्ष 2023 में भारत ने यूएई को 1.61 बिलियन डॉलर मूल्य के प्रसंस्कृत खाद्य और कृषि उत्पादों का निर्यात किया जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापार संबंधों की पुष्टि होती है।

गल्फूड 2025 में भारत की प्रभावशाली उपस्थिति वैश्विक खाद्य उद्योग में देश की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए तैयार है।

# रिपोर्ट: 2029 तक बढ़ेगा इनोवेशन का प्रयोग
## बायोपेस्टीसाइड्स का बाजार दोगुना होने के आसार

**हलधर किसान. नई दिल्ली।** साल 2029 तक दुनियाभर में बायोपेस्टीसाइट्स का बाजार दोगुना होने के आसार के साथ ही आधुनिक टेक्नालॉजी एआई का प्रयोग बढ़ने के आसार नजर आ रहे है। खासतौर पर अनाज, तिलहन और दालों की फसलों को लेकर इसका प्रयोग बढ़ेगा। यह दावा रिसर्च एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट में किया गया ह, जिसमें कहा है कि पूरी दुनिया में जैव कीटनाशक उद्योग तेजी से विकास के दौर से गुजर रहा है।

पूर्वानुमानों के अनुसार 2024 में 7.72 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2029 तक 15.66 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 15.2 प्रतिशत की आशाजनक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर इस क्षेत्र के भीतर गतिशीलता को रेखांकित करती है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियांए विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता नए जैव कीटनाशक विकास, कीट नियंत्रण प्रभावशीलता को अनुकूलित करने और बाजार रणनीतियों को परिष्कृत करने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

## तकनीकी नवाचार विकास को बढ़ावा देते हैं

एआई की परिवर्तनकारी शक्ति सहयोग के माध्यम से स्पष्ट है जो जैव कीटनाशक खोज की गति और दक्षता में नए मानक स्थापित कर रही है। एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा बढ़ाया गया, उत्पाद विकास प्रक्रिया तेज होती जा रही है, जिससे टिकाऊ कृषि समाधान प्रदान करना संभव हो रहा है। ये सफलताएं बाजार को पर्याप्त विकास और नवाचार के लिए आवश्यक गति प्रदान कर रही हैं।

पर्यावरण और आर्थिक अवसर

स्थायी कृषि विधियों की ओर बदलाव जैव कीटनाशक बाजार के भीतर पर्याप्त व्यावसायिक अवसर पैदा कर रहा है। जैसे.जैसे किसान जैव कीटनाशकों को अपनाते हैंए उन्हें रासायनिक विकल्पों पर निर्भरता कम होने, पारिस्थितिकी के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं तक पहुंच और बढ़ी हुई लाभप्रदता का लाभ मिलता है। निर्माता टिकाऊ कृषि इनपुट की वैश्विक मांग का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उत्पाद पोर्टफोलियो और रणनीतिक गठबंधनों में विस्तार हो रहा है।

.....

# रिसर्च: वैश्विक स्तर पर गिलोय की रोग निवारक क्षमता के प्रति लोगों की बढ़ी रुचि

**हलधर किसान ( औषधि )।** देश में आयुर्वेद में गिलोय का सेवन काफी फायदेमंद माना गया है, भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर गिलोय की चर्चा हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस रिसर्च संस्था पबमेड का दावा है कि पिछले एक दशक में गिलोय को लेकर प्रकाशित होने वाले रिसर्च पब्लिकेशन में 376 फीसदी की वृद्धि हुई है। इससे जाहिर होता है कि वैश्विक स्तर पर गिलोय की रोग निवारक क्षमता के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। डेटा के अनुसार गिलोय को लेकर वर्ष 2014 में 243 अध्ययन प्रकाशित हुआ जो वर्ष 2024 में बढ़कर 913 हो गया।

आयुष मंत्रालय द्वारा रिसर्च को बढ़ावा देने को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी देते हुए आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि मंत्रालय आयुष के क्षेत्र में रिसर्च को प्राथमिकता दे रहा है। मंत्रालय दुनिया की प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर आयुर्वेद और हर्बल प्लांट की गुणकारी क्षमताओं को सामने लाने की दिशा में कदम उठा रहा है। हमारी कोशिश आयुर्वेद को मुख्यधारा के स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना है ताकि लोगों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिल सके।

## कोरोना में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में साबित हुई मददगार

आयुष पद्धति के तहत लंबे समय से गिलोय का उपयोग किया जाता रहा है। वैज्ञानिकों को पहले से गिलोय के फायदे के बारे में पता था, लेकिन कोरोना के बाद गिलोय को लेकर होने वाले शोध में अचानक वृद्धि देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि गिलोय में प्राकृतिक तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण है। कई रिसर्च में यह बात सामने आयी है कि गिलोय प्रतिरोधक क्षमता, एंटी वायरल और अन्य रोगों से लड़ने में काफी सहायक है। इस शोध के बाद वैश्विक स्तर पर गिलोय के प्रति वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है। कई शोध में यह बात सामने आयी है कि गिलोय कैंसर, इम्यून संबंधी रोग और अन्य रोगों के उपचार में काफी कारगर है।

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गालिब का कहना है कि वैश्विक स्तर पर गिलोय के वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा हो रही है। दुनिया के विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि गिलोय में रोग ठीक करने की क्षमता है। आने वाले समय में गिलोय कई शोध का विषय बनेगा। फरवरी 2025 में गुजरात यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ साइंस के अध्ययन में पता चला कि गिलोय सर्वाइकल कैंसर के उपचार में मददगार है। जनवरी 2025 में टाटा मेमोरियल सेंटर के शोधकर्ताओं ने भी गिलोय के कैंसर के उपचार को लेकर अध्ययन प्रकाशित किया है।

# उत्तरप्रदेश में अब गंगा के साथ स्थानीय नदियों के किनारे भी होगी प्राकृतिक खेती, सरकार ने तैयार किया खाका, निवेश होंगे 270.62 करोड़ रुपए

## 2022 में मप्र सरकार नर्मदा किनारे प्राकृतिक खेती का कर चुकी है प्रयास, शिवराज सरकार ने बनाई थी योजना

**उत्तरप्रदेश। प्रदेश सरकार ने गंगा के साथ स्थानीय नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने, संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नदियों किनारे भी प्राकृतिक खेती कि जाएगी, जिसके लिए सरकार 270.62 करोड़ निवेश करेगी। इस योजना के तहत अब सिर्फ गंगा ही नहीं स्थानीय नदियों के दोनों किनारे पर 5/5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार 1886 क्लस्टर बनाएगी। इस प्लान पर 270.62 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।**

हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इससे पहले प्रदेश सरकार की कैबिनेट में भी प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना के लिए 1191.51 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। वहीं, हाल ही में पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

### प्राकृतिक खेती से गंगा समेत स्थानीय नदियों को होगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार के प्लान के तहत गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती में जैविक उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रिसाव के माध्यम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जहर इन नदियों में घुलकर उनको प्रदूषित नहीं कर सकेगा।

बता दें कि गंगा के पास के 27 जिलों में पहले से ही नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार गंगा के किनारे के 1000 से अधिक गांवों में प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 54 जिलों में परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। सरकार उद्देश्य निराश्रित गोवंश से सबसे प्रभावित बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाना है।

### प्राकृतिक खेती के पांच हजार क्लस्टर

सीएम योगी के पहले कार्यकाल से ही प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में पांच हजार क्लस्टर्स में 18 हजार से अधिक किसान लगभग 10 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इनमें से करीब 3300 क्लस्टर नमामि गंगे योजना के तहत आते हैं, जहां 6500 हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। इंडो.गंगेटिक क्षेत्र दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि में शामिल है। इसी वजह से नवंबर 2017 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित जैविक कृषि कुंभ में विशेषज्ञों ने गंगा के मैदानी इलाकों को जैविक खेती के लिए आरक्षित करने की सलाह दी थी। यहां बाढ़ के कारण हर साल मिट्टी की उर्वरता बढ़ती हैए जिससे जैविक खेती की संभावनाएं और मजबूत होती हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस योजना को और आगे बढ़ाया गया और अब इसे नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। चूंकि हर साल आने वाली बाढ़ के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी बदलकर उर्वर हो जाती है, इस नाते पूरे क्षेत्र में जैविक खेती की बहुत संभावना है। यही वजह है कि योगी सरकार.2 में गंगा के किनारे के सभी जिलों में जैविक खेती को विस्तार दिया गया। अब सरकार इसे और विस्तार देने जा रही है।

### यहां होती है सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग

आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती हो रही है। जहां एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र इसके दायरे में आ चुका है। यहां पर लगभग सवा पांच लाख किसान ऐसी खेती कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 99000 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ में 85000 हेक्टेयर, केरल में 84000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु आदि में भी इस पर जोर दिया जा रहा है।

**2022 में मप्र सरकार ने भी बनाई थी योजना**

नर्मदा नदी के दोनों ओर पांच किलोमीटर की पट्टी में प्राकृतिक खेती को विकसित किया करने के लिए वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया था। इसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि जिनके पास भी कृषि भूमि है वे अपने खेत में प्राकृतिक खेती का माडल फार्म विकसित करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना निश्चित किया गया ह, उसी तरह प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे कारिडोर विकसित किया जाएगा। मोटे अनाज के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। उद्यानिकी के क्षेत्र में काम करने की बहुत गुंजाइश है।

### ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिलें: केंद्रीय कृषि मंत्री

**हलधर किसान भोपाल।** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भोपाल से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि भवन, नई दिल्ली में उपस्थित अधिकारियों से फसलों की बुआई, उपार्जन, मौसम की स्थिति और जलाशयों के स्तर की जानकारी ली। उन्होंने उपज के थोक एवं खुदरा मूल्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक में विभिन्न उपज की अच्छी पैदावार की संभावनाओं को देखते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि किसानों को अच्छे भाव मिल सकेंण् उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिलना चाहिए और इस दिशा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बजट 2025 में घोषित मखाना बोर्ड के गठन को लेकर भी कृषि मंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और इसके लिए मखाना उत्पादक किसानों से सुझाव भी लिए जाएं, ताकि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्य किए जा सकें।


### हलधर किसान समाचार पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विवरण केसंबंध में घोषणा फार्म-4 (नियम 8 देखिए)

| | |
|---|---|
| 1. समाचार पत्र का नाम | : हलधर किसान |
| 2. समाचार पत्र का पंजीयन संख्या | : MPHIN/2022/ 85285 |
| 3. भाषा/भाषाएं, जिसमें/ जिनमें समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। | : हिन्दी |
| 4. प्रकाशन का स्थान | : 26/1, विवेकानंद कॉलोनी वार्ड नं. 05 खरगोन (म.प्र.) |
| 5. प्रकाशन अवधि | : मासिक |
| 6. मुद्रक का नाम | : कैलाशचंद्र महाजन |
| (क्या भारतीय नागरिक है) | : हाँ |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | |
| पता | : श्री गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन (म.प्र.) |
| 7. प्रकाशक का नाम | : विवेक जैन |
| (क्या भारतीय नागरिक है) | : हाँ |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | |
| 8. संपादक का नाम | : विवेक जैन |
| (क्या भारतीय नागरिक है) | : हाँ |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | |
| 9. सह संपादक का नाम | : - |
| (क्या भारतीय नागरिक है) | : - |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | |
| 10. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के नाम स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो। | : - |

मैं विवेक जैन, एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास केअनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

दिनांक : 01 मार्च 2025

विवेक जैन
प्रकाशक के हस्ताक्षर

# सुरक्षा कवच का काम कर रही पीएम फसल बीमा योजना 9 साल में 19.67 करोड़ किसान भाई.बहन हुए लाभांवित

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

**नई दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 19.67 करोड़ किसान भाई.बहनों को लाभ पहुंचाया गया है। किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 1.65 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने और उनकी आय को स्थिर बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।**

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाढ़, बारिश, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए उन्हें नुकसान की भरपाई की जाती है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भी माना जाता है। 2016 में शुरू हुई पीएम फसल बीमा योजना ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के जरिए 74 करोड़ किसान आवेदनों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और 1.73 लाख करोड़ रुपये किसानों के नुकसान दावों की भरपाई के लिए दिए गए हैं। जबकि नौ साल में किसानों ने फसल बीमा के प्रीमियम के तौर पर लगभग 39,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 बड़ा गेमचेंजर बनकर उभरा है। इसके बाद केंद्र ने किसानों से बातचीत और उनके सवालों के जवाबों के लिए और आसान विकल्प देते हुए व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447 भी दिया है। इन नंबरों के जरिए किसानों तक योजना को पहुंचाने और इसके फायदे बताने में बड़ी कामयाबी मिली है।

## खरीफसीजन में फसल बीमा के 9 करोड़ आवेदन

खरीफसीजन 2024.25 में बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बाद फसलों की भरपाई कराने के लिए किसानों के बीमा कराने के लिए 9 करोड़ आवेदन पहुंचे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन 2024 के लिए 8.69 करोड़ से अधिक किसानों के फसल बीमा कराने के आवेदन पहुंचे हैं। वहीं, रबी सीजन की फसलों के लिए बीमा कराने के लिए किसानों के 8 करोड़ से अधिक बीमा आवेदन पहुंचे हैं।

पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों बीमा कराने पर किसानों को कुछ राशि बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में भुगतान करनी होती है। जबकि, राज्य और केंद्र सरकार भी बीमा कंपनियों को प्रीमियम भुगतान करती हैं। ताकि, किसान पर वित्तीय बोझ न बढ़े। खरीफ फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा रकम का 2 फीसदी प्रीमियम चुकाना पड़ता है। रबी फसलों के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का 1.5 फीसदी प्रीमियम चुकाना पड़ता है।

बागवानी और कमर्शियल फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को कुल राशि का 5 फीसदी प्रीमियम चुकाना होगा।उदाहरण से देखें तो पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के किसान गेहूं फसल का बीमा कराते हैं तो 2 हेक्टेयर फसल के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को किसान सम इंश्योर्ड राशि का केवल 1.5 फीसदी राशि यानी 1800 रुपये प्रीमियम यानी बीमा की किस्त चुकाते हैं। जबकि, प्रीमियम की बाकी 8 फीसदी रकम केंद्र और राज्य सरकार बीमा कंपनी को चुकाती है। फसल का बीमा होने के बाद अगर फसल का नुकसान होता है तो किसान को अधिकतम 1.20 लाख रुपये मुआवजा मिलता है। मुआवजा राशि फसल नुकसान आकलन के आधार पर कम भी हो सकती है।

## 2025.26 के लिए फसल बीमा का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025.26 में पीएम फसल बीमा योजना ; 2025 के लिए रकम आवंटन 12242 करोड़ रुपये किया है। आधिकारिक आंकड़ों के इससे पहले अनुसार केंद्र ने बजट 2023.24 में फसल बीमा के लिए 12949 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इसके बाद 2024.25 के लिए बजट एस्टीमेट 14600 करोड़ रुपये रखा गया, लेकिन बाद में इसे रिवाइज कर 15864 करोड़ रुपये बढ़ाया गया।

# कृषि आदान विक्रेता संघ ने कृषि नवागत उपसंचालक केवड़ा का किया स्वागत, समस्याओं को लेकर कि चर्चा

**हलधर किसान. इंदौर।** स्वच्छता में नंबर-1 शहर इंदौर के कृषि विभाग में नवागत उपसंचालक कृषि चंपालाल केवड़ा के पद्भार संभालने पर ऑल इंडिया एग्री इनपुट डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता व मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल के सचिव संजय रघुवंशी के साथ जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर के अध्यक्ष कृष्णा दुबे, उपाध्यक्ष पूनम हार्डिया, अजब पटेल, सचिव जितेंद्र जैन, भरत खत्री, किशोर पुराणिक, पंकज पटेल आदि ने उपसंचालक श्री केवड़ा को पुष्पगुच्छ भेंटकर पुष्पमालाएं पहनाई। इस दौरान प्रवक्ता श्री रघुवंशी व श्री दुबे जी ने उपसंचालक को आश्वस्त किया कि कृषि आदान विक्रेता और कृषि विभाग एक दूसरे के पूरक है दोनो के समन्वय से इस क्षेत्र में उन्नति और शासन की मंशा का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिनिधिमंडल ने विभाग और कृषि आदान व्यापारियों के बीच में होने वाली परेशानियां व नियम के विषय में भी खुलकर चर्चा की और, जिस पर उप संचालक ने गंभीरता से इन समस्याओं, शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया।

# छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेयरी एक महत्वपूर्ण विकल्प है: सहकारिता मंत्री शाह

**हलधर किसान. नई दिल्ली।**

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। मंत्री शाह ने कहा कि आज जब हम श्वेत क्रांति.2 की तरफबढ़ रहे हैं तब सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। श्वेत क्रांति.1 से अब तक जो हमने हासिल किया है उससे सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को पूरा करना अभी बाकी है। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी है और श्वेत क्रांति.2 की शुरूआत से ही इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत का डेयरी क्षेत्र देश के साथ.साथ ग्रामीण विकास और भूमिहीन और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे सामने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र और 2047 में पूर्ण विकसित देश बनाने के तीन लक्ष्य रखे हैं। इन तीनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हमें हर क्षेत्र में संभावनाओं का शत.प्रतिशत दोहन करने की पद्धति विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर ने आज सर्कुलरिटी के संबंध में गुड प्रैक्टिसिस को 250 दूध उत्पादक संघों तक पहुंचाने की विज़नरी शुरूआत की है। भारत की कृषि प्रणाली छोटे किसानों पर आधारित है और गांवों से शहर की ओर हो रहा पलायन छोटे किसानों की समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रामीण पलायन की समस्या का समाधान करने के साथ छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेयरी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। श्री शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र की सभी संभावनाओं को शत.प्रतिशत एक्सप्लोर करने के लिए होलिस्चिक अप्रोच के साथ काम करने के लिए यह सेमिनार बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विगत 10 साल में देश में खेती में खुशहाली की एक अच्छी शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि गांव से ग्लोबल तक जाने का हौंसला भी बढ़ा है और पद्धतियां भी बनी हैं और कोऑपरेटिव के माध्यम से समूह से सफलता पाने का विश्वास भी बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी चेन ग्रामीण क्षेत्र में ही हो। मोदी सरकार सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि के तीन सूत्रों के साथ.साथ प्रोफिट फार पिपल के मंत्र चरितार्थ कर रही है।

# तीन साल में किसानों को 30 लाख सोलर पंप करायेंगे उपलब्ध, अब पांच रुपये में मिलेगा बिजली का स्थाई कनेक्शनः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

**भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। इसमें मुख्य रुप से 5 रुपये में बिजली का स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चरणबद्ध रुप से पूरे प्रदेश में किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह किसानों की सरकार है। उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार सोलर पंप के माध्यम से किसानों को बिजली उत्पादन में भी आत्म.निर्भर बनाएगी। अगले तीन वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकरए किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाएगी। प्रतिवर्ष 10.10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीद कर उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे किसानों को संबोधित कर रहे थे।**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के प्रत्येक अंचल से आए किसानों का पुष्प.वर्षा कर स्वागत अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कृषकों ने साफा, गज मालाए शॉल.श्रीफल और प्रतीक.चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी एवं हल की प्रतिकृति भेंट कर अभिनंदन किया। कृषकों की ओर से होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने समस्त अतिथिगण को स्मृति चिन्ह के रूप में राम दरबार भेंट किये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव किसानों के साथ है और उनके हित में निरंतर कार्य कर रही है। हम 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद रहे हैं, इसमें 175 रुपये बोनस राशि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2003.04 में प्रदेश में गेहूं खरीदी का सरकारी दाम मात्र 447 रुपए था जो राज्य सरकार ने बढ़ा कर 2 हजार 600 प्रति क्विंटल किया है।

## धान उपार्जन पर मिलेगी 4 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि

सरकार वर्ष 2024 के लिये धान उपार्जन पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलर पंप के माध्यम से किसानों को स्थाई कनेक्शन भी दिए जाएंगे। हाल ही में अस्थाई कनेक्शन वाले डेढ़ लाख किसानों को स्थाई कनेक्शन दिलवाए गए हैं और इसकी राशि भी कम की गई है। तीन हॉर्स पॉवर वालों को सोलर पंप की 5प्रतिशत राशि, 5 से 7.50 हॉर्स पॉवर के लिए 10 प्रतिशत राशि देना होगी।

यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का किसानों के प्रति प्रेम है। हर गरीब, जरूरतमंद के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है। दो लाख करोड़ रुपए के व्यय से 100 करोड़ से अधिक लोगों को वर्ष 2028 तक अन्न देने की व्यवस्था की गई है।

## फसल चक्र में बदलाव करें किसान

यह कृषकों स फसल चक्र में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धान के बदले में मूंगफली और प्राकृतिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जैविक खेती से मध्यप्रदेश अपनी अलग पहचान स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जीआईएस भोपाल में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में उत्पादित कपास से क्रांति आने वाली है। किसान परिवार के व्यक्ति को रोजगार देने वाली टेक्सटाइल मिलों को 5 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। गेहूं और धान पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के समान ही दुग्ध उत्पादन पर भी प्रोत्साहन स्वरूप बोनस प्रदान किया जाएगा। आने वाले समय में उन्नत कृषि यंत्रए उन्नत बीज और कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर पर कृषि मेले लगाए जाएंगे। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार वैश्विक स्तर पर उपलब्ध श्रेष्ठतम बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत एक लाख करोड़ की केन.बेतवा लिंक परियोजना और 70 हजार करोड़ से चंबल.काली सिंध.पार्वती लिंक परियोजना का क्रियान्वयन जारी है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के सहयोग से तापी नदी पर तीसरी नदी जोड़ो परियोजना आरंभ होगी।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि किसान भारतीय अर्थ व्यवस्था की बैकबोन हैं। किसानों को मिल रही सुविधाओं से राज्य पुनः कृषि में देश में सिरमोर बनेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गेहूँ और धान के बारे में घोषणा कर किसानों की मेहनत को सम्मान दिया है। खजुराहो सांसद वी.डी शर्मा ने कहा कि किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव आभार व्यक्त करने का निर्णय सराहनीय है। इस ऐतिहासिक फैसले से किसान परिवारों में प्रसन्नता का संचार हुआ। किसान मोर्चा के अध्यक्ष तथा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा किसान हित में लिए गए निर्णयों के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से आभार माना। मुख्यमंत्री निवास में किसान आभार सम्मेलन के अवसर पर ऊर्जा, उद्यानिकीए खाद्य नागरिक आपूर्ति, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई।

खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, नगर निगम भोपाल अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

45 वर्षो से आपके विश्वास का साथी
Since 1975
बीज भंडार ©
उन्नत खेती के उत्तम बीज
हमारे यहॉ सभी कम्पनियों के उन्नत किस्मों के उत्तम बीज मिलते है।
ब्रांच - खरगोन, खंडवा, अंजड, महु, राजपुर, धामनोद, कुक्षी, मनावर,
छींदवाडा, इन्दौर, जबलपुर, मण्डलेश्वर, कालापीपल, पुंजापुरा
बीज भंडार की फेंचाइजी लेने के लिए सम्पर्क करें – 78794 28271

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।